(b) if so, what steps are being pro posed to be taken to promote tourism in these N.E. States; and

(c) whether the Central Govern ment have received any representa tion from these States on this issue and if so, what action has been taken thereon?

THE MINISTRY OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): (a) Yes, sir.

(b) and (c) Recently Central Government have relaxed restrictions on the entry of tourists in some aleas of North Eastern, region.

उच्च न्यायलयों के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

1219. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों के उन मुख्य न्यायाधीशों के नाम क्या हैं, जो अपने ही राज्य में कार्यरत हैं और जिनके सेवानिवृत्त होने में अभी दो वर्ष से अधिक का समय है ;

(ख) उन्हें अब तक स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनका स्थानांतरण कब तक कर दिया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) कोई नहीं। इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति के पद रिक्त हैं, जहां योग्यतम अवर न्यायाधीश उक्त पदों के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"फेरा" का अतिक्रमण किए जाने के मामले

1220. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध पिछले तीन महीनों के दौरान "फेरा" के अंतर्गत कार्यवाही की गई है और उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : दिसम्बर, 1989 से फरवरी, 1990 तक पिछले तीन महीनों में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मामलों का आंकड़ा इस प्रकार है :—

(i) ली गई तलाशियों की संख्या .	688
(ii) पकड़ी गई भारतीय मुद्रा (लाख रुपयों में) . .	192.93
(iii) पकड़ी गई विदेशी मुद्रा (लाख रुपयों के समकक्ष) .	227.61
(iv) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या .	92
(v) कोफपोसा के अंतर्गत रोके गए व्यक्तियों की संख्या	31
(vi) लगाए गए जुर्माने की राशि (लाख रुपयों में) .	517
(vii) वसूल किए गए जुर्माने की राशि (लाख रुपयों में)	63 61

वस्त्र नीति के संबंध में श्वेत-पत्र

1221. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र नीपि पर कोई श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने का इरादा रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार ने जून, 1985 की वस्त्र नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया था । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है ।

Plan for a voluntary special fund Presented to IMF

1222. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) what is the impact of the Plan for a Voluntary Special Fund recently presented to the IMF by the Indian Director, which would enable the Third World countries who are in arrears, to get further aid;

(b) whether the developed countries are agreeable to this plan if so, what are their reactions; and

(c) what are the details of the progress made so far in the matter?

THE FINANCE MINISTER (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) At present the burden of additional charges on members' overdue financial obligations to the IMF are met by both debtor and creditor countries through higher charges from the former and reduced remuneration to the latter thereby allowing the members who are neither borrowers nor creditors to escape the burden. Besides, under the present burden sharing arrangement the debtor countries, most of them poor developing ones, bear burden far in excess of their quota share whereas creditors countries most of them developed, share less than their quota share. In contrast, the proposal made by our chair in the Board of IMF envisages the broadening of the scope of burden sharing mechanism by making the entire membership participate and thereby making the arrangement more equitable.

(b) and (c) The industrial countries were not very enthusiastic about it as the contributions were to be voluntary and they expressed the view that the required amounts may not be forthcoming.

Resignation of Mr. G. Ramaswamy, Government Counsel

1223. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the Hindustan Times dated the 24th February, 1990 to the effect that the Law Ministry have obtained the resignation of the Government counsel, Mr. G. Ramaswamy assisting the Kuldip Singh Commission; and

(b) what are the facts and circumstances leading to the change of counsel of the Commission at this late stage?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI) : (a) Yes, sir. The attention of the Government has been drawn to this news item.

(b) There is no change of counsel of the Commission.

IDBI term loans for cooperative spin-ing mills in Maharashtra

1224. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI; Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether Maharashtra Government has repeatedly requested the Industrial Development Bank of India to sanction term loans to the cooperative spinning mills in the State to enable them to go under commercial production; and